नईदुनिया

डीजीसीए एयर इंडिया एक्सप्रेस चालक दल की हड़ताल मामले की जांच कर रहा, मंत्री बोले- होगी कार्रवाई

नई दिल्ली ।

विमानन नियामक डीजीसीए मई में एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल की हड़ताल की घटना की जांच कर रहा है। इसके कारण कई उड़ानें रद्द हुई थीं और नियमों का अनुपालन नहीं करने पर एयरलाइन पर जुर्माना लगाया जाएगा। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने इसकी जानकारी दी। लोकसभा में उड़ानों के रद्द होने से संबंधित प्रश्नों के जवाब में, नायडू ने कहा कि मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई रद्दीकरण या देरी न हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) यह सुनिश्चित करने के लिए थीं कि प्रभावित यात्रियों को मुआवजा मिले। नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, हम स्वीकार करते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एक मुद्दा रहा है... चालक दल के साथ कुछ आंतरिक मुद्दे थे क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर एशिया इंडिया में विलय हो रहा था और इस कारण बड़े पैमाने पर हड़ताल (7 मई को) हुई। हड़ताल के कारण कई उड़ानें रद्द हुईं। उन्होंने कहा, एक बार जब यह मुद्दा शुरू हुआ तो मंत्रालय इसमें शामिल हो गया, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने एयरलाइन, चालक दल के सदस्यों और अन्य चीजों के साथ काफी चर्चा की और इसे सुलझा लिया गया... एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी भी हुई थी। सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण, चालक दल के सदस्यों के डेटा जो एयरलाइन के पास होनी चाहिए थी, उसमें कुछ समस्या थी और वे मैन्युअल रूप से (डेटा) दर्ज करने की कोशिश कर रहे थे ... सब कुछ सामान्य स्थिति में वापस आने के लिए, (इसमें) कुछ समय लगा। नायडू ने कहा कि अगर विमानन कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं तो मंत्रालय दखल देता है और सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को किसी अन्य उड़ान में समायोजन मिले या उन्हें पैसे रिफंड किए जाएं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा, डीजीसीए एयर इंडिया एक्सप्रेस की हड़ताल की घटना की गहराई में जा रहा है और मामले की जांच कर रहा है। अगर एयरलाइंस की ओर से कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम उन्हें दंडित करने जा रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि यात्री ही सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

न्यूज ब्रीफ

एंजल कर हटने से बढ़ेगा नवाचार, विदेशी निवेश भी आएगा; विवाद और मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी

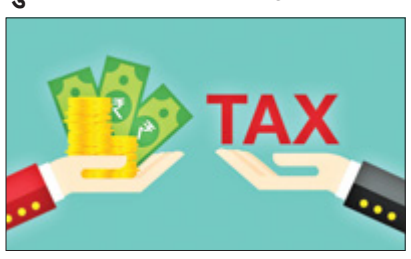

नई दिल्ली । स्टार्टअप के लिए एंजल कर हटाने के सरकार के फैसले से विदेशी निवेश आकर्षित करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने के साथ स्टार्टअप तंत्र को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, यह एक लंबित मुद्दा था, क्योंकि यह कर देश में आने वाले निवेश पर लगाया जाता था। इस तरह के विदेशी निवेश पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। एंजल कर हटाने से विवाद और मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी। जरूरी था कर हटाना सचिव ने कहा, निवेशक संभावित नए नवाचार पर निवेश करता है और एंजल कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इस कारण भारत में एक 'वास्तविक रूप से अच्छे' विचार को समर्थन नहीं मिल रहा था। साथ ही, यह लोगों को विदेश से पैसा लाने के लिए मजबूर कर रहा था। एंजल कर के कारण भारत में एफडीआई कम हो जाता है। इससे ऐसी व्यवस्था बनती है, जहां लोग देश के बाहर रहते हैं और फिर लंबे समय बाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि बाजार यहीं है। क्या है एंजल कर सरकार एंजल कर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप की ओर से जुटाई गई धनराशि पर तब लगाती है, जब उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। इस पर 30 फीसदी से अधिक कर लगता है।

80 करोड़ की बैंक जमा और डीमैट होल्डिंग्स फ्रीज; फॉरेक्स ट्रेडिंग एप मामले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 80 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बैंक जमा और डीमैट होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर निवेशकों से 500 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। ईडी ने दी जानकारी ईडी ने कहा कि उसने ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग एप और वेबसाइट के मामले में 22 जुलाई को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुरुग्राम में छापे मारे गए थे। ऑक्टाएफएक्स पर विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों से धोखे से प्राप्त धन को सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के रूप में डाला गया है, ताकि उन्हें वैध निधि के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, ऑक्टाएफएक्स ने निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और एस्टोनिया में स्थित संस्थाओं का उपयोग किया। ईडी के अनुसार, ऑक्टाएफएक्स ने कई शेल या नकली कंपनियां स्थापित कीं और विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के बहाने उनके बैंक खातों का उपयोग किया। 1000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया एजेंसी के अनुसार, ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाएफएक्स और उनकी संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया है, जिससे भारतीय क्षेत्र से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया है। इन निधियों का एक हिस्सा शेल संस्थाओं की मदद से जटिल लेनदेन के जाल के माध्यम से स्थांतरित किया गया था और फर्जी माल ढुलाई सेवाओं, सेवाओं के आयात आदि की आड़ में अपनी संबंधित संस्थाओं को विदेश में भेजा गया था।

निवेश प्रस्तावों की मंजूरी के लिए सख्त की जाएगी समयसीमा, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आएगी तेजी

नई दिल्ली । सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए सख्त समयसीमा तय करेगी। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी आएगी। डीपीआईआईटी सचिव ने कहा, इन मंजूरियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। फिर भी इसमें देरी हो रही है क्योंकि एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है। सचिव ने कहा, मंजूरी व अनुमोदन की प्रक्रिया को छोटा करने का विचार है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को खत्म करने के बाद एफडीआई नीति और फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) विनियमों के तहत विदेशी निवेश के लिए मंजूरी देने का कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंप दिया गया है।

एलटीसीजी टैक्स में बदलाव पर सीबीडीटी चेयरमैन ने साफ की तस्वीर, बोले- यह व्यावहारिक तौर पर फायदेमंद

नई दिल्ली ।

बजट 2024-25 में लंबी अवधि के लिए रखी गई गृह संपत्तियों की बिक्री से अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर की दरों को कम कर दिया गया है, लेकिन करदाताओं के लिए उपलब्ध इंडेक्सेशन के लाभ को हटा दिया गया है। कुछ वर्गों ने इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर के प्रभावित होने पर चिंता जाहिर की है। अब सीबीडीटी चेयरमैन ने इस पर स्थिति साफ की है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि रीयल एस्टेट लेनदेन से इंडेक्सेशन लाभों को हटाना करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसे सादे गणित के बजाय वास्तविक बाजार की गतिशीलता के आधार पर देखा जाना चाहिए।

देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के प्रमुख ने बजट के बाद साक्षात्कार में पीटीआई भाषा से कहा कि विभाग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में घोषित किए गए उपायों से पहले इस बारे में कुछ गणना की थी। अग्रवाल ने यह भी बताया कि नई प्रणाली कहती है कि यहां करदाता पर कम कर दायित्व होगा। बजट 2024-25 में लंबी अवधि के लिए रखी गई गृह संपत्तियों की बिक्री से अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर की दरों को कम कर दिया गया है, लेकिन करदाताओं के लिए उपलब्ध इंडेक्सेशन के लाभ को हटा दिया गया है।

एलटीसीजी (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) टैक्स की दर को इंडेक्सेशन सुविधा हटाकर 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। इंडेक्सेशन ऐसी परिसंपत्तियों के खरीद मूल्य पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने का एक तंत्र है।

बजट में एलटीसीजी में बदलाव की घोषणा के बाद कई वर्गों ने चिंता जाहिर की है कि इंडेक्सेशन को दूर करने से रियल एस्टेट बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस अग्रवाल ने कहा कि व्यावहारिक रूप से, ज्यादातर मामलों में, नई योजना फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न तबकों और करदाताओं की ओर से पूंजीगत लाभ व्यवस्था को सरल बनाने की मांग की जा रही है।

एलटीसीजी में बदलाव का मकसद प्रक्रिया को सरल बनाना: सीबीडीटी चेयरमैन - सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि बजट के इस कदम का मकसद इस प्रक्रिया को सरल बनाना है क्योंकि कोई भी जटिल

ढांचा अपने साथ विवाद भी लेकर आता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख ने कहा कि व्यावहारिक रूप से देखते हैं कि वर्तमान में बाजार में क्या होता है।

अचल संपत्ति का मामला लें, संपत्ति की दरें या लाभ पिछले दस वर्षों में काफी बढ़ गए हैं। अब, पिछले 10 वर्षों में नई व्यवस्था के साथ अपने इंडेक्सेशन की तुलना करें, मान लीजिए कि आपने 2014 में एक संपत्ति खरीदी है, और आप इसे 2024-25 में बेच रहे हैं। तो इंडेक्सेशन का लाभ केवल 1.5 गुना होगा। मान लिए कि यदि संपत्ति एक्स है, तो मूल्यांकन की सूचकांक लागत 1.5 गुना होगी। 10 साल में इसमें केवल 1.5 गुना की वृद्धि होगी।

सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि हमने (सीबीडीटी और आयकर विभाग) कुछ गणना की है और पाया है कि यदि संपत्ति की दर 10 साल में तीन गुना बढ़ती है तो बजट में घोषित नई कर व्यवस्था फायदेमंद है। अग्रवाल ने कहा, व्यावहारिक रूप से, ज्यादातर मामलों में, संपत्ति की दरें तीन गुना से अधिक बढ़ गई हैं। उस गणित को छोड़िए जो कहता है कि अगर दस साल में प्रॉपर्टी रेट दो गुना या डेढ़ गुना बढ़ गया है तो क्या होता है वगैरह... वास्तविकता यह है कि संपत्ति की दरें तीन गुना से अधिक हो गई हैं और रियल्टी क्षेत्रों में ... टियर वन और टियर टू शहर... सर्किल रेट बढ़ गए हैं... यहां तक कि बाजार की दरें भी।

नई कर व्यवस्था में करों की बाध्यता कम - सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा, 2001 को आधार मानें तो 20-25 वर्षों में संपत्ति की दरें बहुत अधिक बढ़ गई हैं, और अब 2024 में, इन 23 वर्षों में, यदि संपत्ति की दर सात गुना या साढ़े सात गुना बढ़ गई है, तो नई व्यवस्था फायदेमंद है। गणित एक तरफ है, जब आप वास्तविक बाजार में आते हैं, तो आप पाते हैं कि नई कर व्यवस्था बेहतर है। अग्रवाल ने कहा कि प्रभावी रूप से (नई व्यवस्था में) कर की बाध्यता कम है।

सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा, हम लंबे समय से इस इंडेक्सेशन शासन के साथ रह रहे हैं और हमें इसकी आदत हो गई है। लेकिन, अगर हम वास्तव में इसका विश्लेषण गणित के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वास्तविक बाजार की गतिशीलता को देखते हुए करना शुरू करते हैं, तो कोई भी समझ सकता है कि यह योजना बेहतर है। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि नई व्यवस्था का मकसद प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिसे समझने में आसान (करदाता के लिए) होना चाहिए, क्रियान्वित करने में (कर विभाग के लिए) आसान होना चाहिए और इसमें प्रावधानों की बहुलता से पैदा होने वाले विवादों को कम से कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पुरानी संपत्तियों के मामले में उचित बाजार मूल्य के 2001 के इंडेक्सेशन के अनुसार पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। बजट में 2001 से पहले खरीदी या विरासत में मिली संपत्तियों पर करदाताओं के लिए इंडेक्सेशन लाभ को बरकरार रखा गया है। हालांकि, एलटीसीजी इंडेक्सेशन प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बजट में एक अक्टूबर से वायदा व विकल्प (एफएंडओ) कारोबार पर लगने वाले प्रतिभूति सौदा कर (एसटीटी) में बढ़ोतरी के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर चेयरमैन ने कहा कि यहां लेनदेन में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा, यह देखा गया कि हर कोई भाग ले रहा था (एफएंडओ में) ... इसमें अधिक जोखिम शामिल हैं और यह भी तथ्य है कि अगर इतनी भागीदारी है, तो क्या हम वास्तव में उससे कुछ राजस्व प्राप्त कर सकते हैं यह एक कारण है, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम इसे बढ़ावा देते हैं हमने एक प्रवृत्ति देखी है, और हमें कहना चाहिए कि यह ठीक है या हमें एक ऐसी व्यवस्था के साथ आना चाहिए जो (प्रणाली) को सामान्य करे। बजट में एसटीटी में वृद्धि का एलान आर्थिक सर्वेक्षण में डेरिवेटिव कारोबार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी पर चिंता जताए जाने के एक दिन बाद किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि विकासशील देश में सट्टा व्यापार का कोई स्थान नहीं है। यह भी कहा गया है कि एफएंडओ कारोबार में खुदरा निवेशक भागीदारी में तेज वृद्धि संभवत: लोगों की जुए के प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति से प्रेरित है।

सोने का भाव गिरकर 67,900, चांदी 81,500 रुपए के करीब

नई दिल्ली ।

सोने और चांदी के वायदा भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 67,900 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 81,500 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वैश्विक बाजार में भी सोने व चांदी के वायदा भाव में नरमी देखी जा रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 937 रुपये की गिरावट के साथ 68,015 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 1,058 रुपये की गिरावट के साथ 67,894 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 393 रुपये की गिरावट के साथ 84,501 रुपये पर खुला। इस समय यह 3,390 रुपये की गिरावट के साथ 81,504 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2,398.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,415.70 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 44.50 डॉलर की गिरावट के साथ 2,371.20 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 29.07 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 29.31 था। इस समय यह 1.24 डॉलर की गिरावट के साथ 28.07 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

तेलंगाना की सरकार ने 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया

हैदराबाद ।

तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.91 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ बजट पेश किया। बजट में राजस्व व्यय 2.21 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 33,487 करोड़ रुपये है। कुल राजस्व 2,90,814 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 57,000 करोड़ रुपये से अधिक के ओपन मार्केट लोन शामिल थे। इस क्षेत्र को इतना मिला तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि के लिए 72,659 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग के लिए 21,292 करोड़ और सिंचाई के लिए 22,301 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है।

29,816 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना का कर्ज 6.71 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच गया है। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार का कर्ज बिना किसी विकास के 10 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद 35,118 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया, जबकि 42.892 करोड़ रुपये के कर्ज (मूलधन और ब्याज दोनों) चुकाए गए।

तेलंगाना का कर्ज बढ़ा

विक्रमार्क ने कहा कि इस बजट में हमने पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए

स्टारलिंक सेवा अब एक हजार से ज्यादा विमानों में शुरू: एलन मस्क

सैन फ्रांसिस्को ।

स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बताया कि किफायती इंटरनेट सेवा स्टारलिंक अब एक हजार से ज्यादा विमानों में शुरू हो गई है।कंपनी के अनुसार, स्टारलिंक यात्रियों को विमान में कदम रखते ही हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा।

एलन मस्क ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, विमान में स्टारलिंक का उपयोग करने से ऐसा लगता है जैसे आप हाई-स्पीड ग्राउंड फाइबर कनेक्शन पर हैं।

एलन मस्क ने हाल ही में बताया कि अफ्रीका का सिएरा लियोन देश स्टारलिंक से जुड़ने वाला 100वां और 10वां अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है।

मई में कंपनी ने इंडोनेशिया और फिजी में स्टारलिंक लॉन्च किया था। एलन मस्क के अनुसार, स्टारलिंक के साथ हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा का ऑर्डर देने के लिए किसी लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है।

सेटेलाइट-बेस्ड इंटरनेट सर्विस को द्वीप राष्ट्र में इंटरनेट सेवा देने के लिए श्रीलंका से शुरुआती मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि, इंटरनेट सेवा को अभी तक भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है।

कमर्शियल पहलू की जांच पूरी हो गई है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। साथ ही, तकनीकी जरूरतों को भी देश में लाइसेंसिंग नियमों के हिसाब से परखा गया है।

एक बार स्टारलिंक को मंजूरी मिल जाने के बाद, उसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सर्विसेज लाइसेंस जारी किया जाएगा, जो देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए जरूरी है।

इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार को बढ़ाने रोडमैप तैयार, हीरो मोटोकॉर्प खेलने जा रही बड़ा दांव : गुप्ता

नई दिल्ली ।

हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता ने कहा कि कंपनी के पास अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार को तेजी से बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट की लीडरशिप की ओर देखते हुए, हीरो मोटोकॉर्प वित्त वर्ष 2025 में किफायती मॉडल पेश करने की योजना बना रही है, जो कंपनी के पास मौजूद वीडा वी1 प्रो के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएगा।

कंपनी की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि कंपनी इस वित्तीय वर्ष में मध्यम और किफायती सेगमेंट में उत्पाद लॉन्च करेगी। लान्च होने वाले नए प्रोडक्ट्स का मुकाबला टीवीएस और ओले के किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों से होगा। हीरो मोटोकॉर्प की वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज की कीमत 1-1.5 लाख रुपये के बीच है, जो सब्सिडी मिलने के बाद की कीमत है। कंपनी ने एथर एनर्जी के साथ मिलकर वीडा ईवी के लिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है। इसके अलावा जीरो मोटरसाइकिल के साथ साझेदारी के तहत कंपनी विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी।

हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने कहा, मैं भारत में अग्रणी इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक के रूप में वीडा वी1 के उदय को देखकर विशेष रूप से प्रसन्न हूं, और मुझे वैश्विक बाजारों में इसके भविष्य के लॉन्च की उम्मीद है, जहां यह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। हीरो मोटोकॉर्प ने पहले ही अपने ईवी स्कूटर वीडा की उपस्थिति को तीन से बढ़ाकर 100 से अधिक शहरों तक कर दिया है।

गुप्ता ने शेयरधारकों को बताया, हमारे सीआईटी जयपुर और टेक सेंटर जर्मनी में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में सभी क्षेत्रों में एक विजयी पोर्टफोलियो बनाने के लिए इनोवेशन चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कंपनी अधिक प्रीमियम उत्पादों को आगे बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय, सहायक उपकरण और व्यापारिक व्यवसायों को बढ़ाने की भी योजना बना रही है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रेंज की शुरुआत की ओर बढ़ रही है।

निजी क्षेत्र को रोजगार के लिए सरकार के साथ काम करना चाहिए: आनंद महिंद्रा

नई दिल्ली । महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत के निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन तथा युवाओं को रोजगार योग्य बनाने की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास के अभाव में देश का जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ-साथ वृद्धि के महत्व को पहचानती है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जीडीपी में हमारी वृद्धि के मामले में हम दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय हैं। हमारे भविष्य को लेकर आश्वस्त होने के कारण हम निवेश के लिए दुनिया का पसंदीदा गंतव्य हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इस वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी तेजी आए। महिंद्रा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित योजनाएं आशाजनक हैं। निजी क्षेत्र से भी अपनी भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए महिन्द्रा ने कहा कि उसे आगे आकर रोजगार तथा रोजगार योग्यता दोनों में निवेश करके अपनी भूमिका निभानी होगी।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017